PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 291 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार, 07 मई, 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

महिलाओं को मिला मालिकाना हक, पारदर्शिता से घटा भ्रष्टाचार

बेघरों का सपना साकार | 19.46 लाख से अधिक को मिली पक्की छत

राजस्थान में पीएम आवास योजना-ग्रामीण का असर, 85% लक्ष्य हुआ पूरा

मनोहरसिंह खोखर। जयपुर

3283 करोड़ के बजट से तेज हुआ निर्माण, 2025-26 में सबसे ज्यादा फंड जारी, केवल मकान नहीं, गैस-जल-शौचालय जैसी सुविधाओं से बदली जिंदगी

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में नई ईबारत लिखी जा रही है। पीएमएवाईजी योजना में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 19.46 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस लक्ष्य को गति देने के लिए केन्द्र सरकार ने राजस्थान के लिए 3283 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के लिए 24.97 लाख मकानों का लक्ष्य रखा था, जिसमें से 24.32 लाख को स्वीकृति मिल चुकी है। अकेले वर्ष 2025-26 में 1641 करोड़ रुपये की सर्वाधिक राशि जारी की गई है। सरकार ने वर्ष 2029 तक 'सभी के लिए आवास' का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। पिछले एक दशक में ग्रामीण विकास के बजट आवंटन में 211% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना का लक्ष्य समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को मदद पहुंचाना था। जिनके पास रहने को अपना कोई घर नहीं था। जो घास-फूस, मिट्टी या प्लास्टिक की छत वाले (एक या दो कमरों के) मकानों में रहते थे। SECC-2011 (सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना) के आंकड़ों के आधार पर ऐसे गरीब परिवार का चयन किया था।

योजना ने बदली ग्रामीण भारत की तस्वीर :

अब लाभार्थियों को ईंट, सीमेंट और कंक्रीट का मजबूत पक्का घर मिल रहा है। अब केवल घर नहीं, बल्कि साथ में उज्ज्वला का गैस, इज्जत घर (शौचालय) और नल से जल भी मिल रहा है। साथ ही पैसा अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आ रहा है, जिससे भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है। इसके अलावा घरों का मालिकाना हक महिलाओं को मिलने से उनका समाज में सम्मान बढ़ा है। राजस्थान की बात करें तो 19.46 लाख से अधिक परिवारों का 'पक्की छत' का वर्षों पुराना सपना अब हकीकत बन चुका है।

शुरुआत थी चुनौतीपूर्ण, अब लक्ष्य के करीब

योजना शुरू होने (2016) से पहले ग्रामीण भारत में आवास की स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण थी। करोड़ों परिवार टपकती छतों और असुरक्षित दीवारों के नीचे रहने को मजबूर थे। पुराने मकानों में शौचालय, साफ पानी और बिजली के कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। पिछली योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में बिचौलियों का बोलबाला था और पैसा पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। वही बजट कम होने के कारण मकानों का निर्माण बहुत धीमी गति से हो रहा था, लेकिन अब लक्ष्य पूरा होने के कगार पर है।

2025-26 में सबसे ज्यादा 1641 करोड़ की राशि जारी

योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की ओर से 3283 करोड़ रूपये से अधिक का बजट आवंटन किया गया है। वहीं, गत 3 वित्तीय वर्षों में मकानों के निर्माण के लिए प्रदेश को 2771 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। इसमें से केवल 1641 करोड़ रूपए की सर्वाधिक राशि वर्ष 2025-26 में ही जारी हुई।

पीएमएवाई-जी योजना में बेघर और जरूरतमंद ग्रामीणों को सस्ते आवास के लिए सहायता उपलब्ध करवाना ही इसका उद्देश्य है। यह योजना निर्धनता और सामाजिक-आर्थिक असमानता में लगातार कमी लाने के साथ ही बुनियादी सेवाओं की पहुंच में निरन्तर सुधार कर रही है।

केवल छत ही नहीं, आर्थिक और बुनियादी सुविधाएं भी :

योजना केवल छत प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करती है। मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख की सीधी सहायता किस्तों में दी जाती है। 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत शौचालय, 'उज्ज्वला योजना' के तहत गैस कनेक्शन और 'हर घर जल' मिशन के तहत नल कनेक्शन को इस आवास के साथ जोड़ा गया है। लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी (करीब 20,000 अतिरिक्त) भी प्राप्त होती है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज जयपुर में मनाएगी सेना

ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म करेंगे रिलीज

लोक टुडे। जयपुर

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ सेना जयपुर में मनाएगी। जयपुर स्थित साउथ वेस्टर्न कमांड में गुरुवार को कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख जयपुर आएंगे। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म भी रिलीज की जाएगी।

भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तब पाकिस्तान से लगती लंबी सीमा, सैन्य ठिकानों की मौजूदगी और सीमावर्ती जिलों की संवेदनशीलता के कारण ऑपरेशन सिंदूर का प्रमुख केंद्र राजस्थान रहा था। ऐसे में सेना ने फिर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए राजस्थान को चुना है।

ऑपरेशन से जुड़ी फिल्म करेंगे रिलीज

जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार दोपहर 12 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ खातीपुरा स्थित सप्त शक्ति कमांड में मीडिया को संबोधित करेंगे। वहीं शाम 5 बजे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी फिल्म को रिलीज किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो इस फिल्म के कई शॉट्स रियल हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के समय शूट किया गया था।

एस-400 के 5 नए स्क्वॉड्रन खरीदने की तैयारी

नई दिल्ली

भारत सरकार एस-400 मिसाइलों के 5 नए स्क्वॉड्रन खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके एक स्क्वॉड्रन में 8 लॉन्चर होते हैं और हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल कंटेनर होते हैं। इस हिसाब से करीब 32 बड़ी मिसाइलें मिलेंगी। पिछले साल 7 से 10 मई के बीच चले ऑपरेशन सिंदूर में हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की एस-400 मिसाइलों ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर कहर बरपाया था, अब हमारे रक्षा बेड़े में उनकी तादाद बढ़ने जा रही है। खरीदी की दिशा में रूस के साथ चर्चा में सकारात्मक प्रगति हुई है। वायु सेना के लिए 5 एस-400 का पहला सौदा 2018 में हुआ था। 3 सिस्टम्स मिल चुके हैं। रूस ने आश्वस्त किया है कि शेष दो सिस्टम और ऑपरेशन सिंदूर में खर्च हुई बैटरी की मिसाइलें भी अगले 6 माह में दे देंगे। रूस के मुताबिक इसके बाद नए स्क्वॉड्रन आएंगे।

वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा, कैबिनेट की मंजूरी

अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा-जुर्माना; जन-गण-मन से पहले गाया जाएगा

नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज,संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा। कानून में बदलाव और सजा का प्रावधान सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

सरकार ने जारी की गाइड लाइन

केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की। गाइड लाइन के अनुसार, वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है। प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए।

ईरान जंग 48 घंटे में खत्म हो सकती है: 14 शर्तों का समझौता तैयार, अमेरिका ईरानी प्रॉपर्टी लौटाएगा

ईरान होर्मुज खोलेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकेगा

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका और ईरान में युद्ध खत्म करने और परमाणु बातचीत का रास्ता तय करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 48 घंटे के भीतर सीजफायर को लेकर सहमति दे सकता है। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट वाला समझौता (MOU) तैयार है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। समझौते की अहम शर्तें जानिए सबसे पहले युद्ध खत्म करने की घोषणा होगी 30 दिनों तक दोनों देशों की विस्तृत बातचीत होगी इसमें होर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील जैसे मुद्दे होंगे दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए इस्लामाबाद या फिर जिनेवा जैसे शहरों पर विचार हो रहा है।ड्राफ्ट के मुताबिक, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक सकता है। बदले में अमेरिका धीरे-धीरे प्रतिबंध कम करेगा और ईरान के जब्त किए हुए अरबों डॉलर जारी कर सकता है। साथ ही, होर्मुज में दोनों तरफ से लगाई गई पाबंदियों में भी ढील दी जाएगी। हालांकि सबसे बड़ा विवाद न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की अवधि को लेकर है। ईरान 5 साल का प्रस्ताव दे चुका है, जबकि अमेरिका 20 साल चाहता था। अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जिसमें 12 से 15 साल तक की अवधि पर बात चल रही है।

होर्मुज पर यूएन में नया प्रस्ताव

अमेरिका ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए NSC में नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें ईरान से हमले, माइंस बिछाना और टोल वसूली तुरंत रोकने को कहा गया है।

यूएई पर फिर हमला

ईरान ने UAE पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोनों से हमला किया। UAE ने कहा कि उसके डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल और ड्रोन को आसमान में ही रोक लिया।

लेबनान में सिर्फ नाम का सीजफायर, इजराइली हमले जारी

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में सीजफायर सिर्फ नाम का रह गया है, जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। इजराइल ने लोगों को जगह खाली करने के आदेश दिए गए और कई हवाई हमले भी किए गए। सबसे खास बात यह है कि अब हमले सिर्फ दक्षिण लेबनान तक सीमित नहीं रहे अब समुद्र किनारे से लेकर अंदरूनी इलाकों तक बमबारी की जा रही है। वहीं हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले कर रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने रॉकेट और ड्रोन से हमला किया है। इजराइल ने भी माना है कि उनके कम से कम 2 सैनिक घायल हुए हैं।

यूएसएस जॉर्ज बुश वॉरशिप होर्मुज पहुंचा: अमेरिका ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वॉरशिप भेजा। इसका मकसद उन जहाजों को सुरक्षित निकालना था, जो होर्मुज में फंसे हुए हैं।

फुजैराह हमले के बाद भारत नाराज: भारत ने कहा कि तीन भारतीय नागरिकों का घायल होना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा रोकने की अपील की है।

बंगाल में 9 को भाजपा सरकार की शपथ, विजय ने तमिलनाडु में पेश किया सरकार बनाने का दावा

लोक टुडे। कोलकाता

बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा में भाजपा और टीएमसी के 2-2 कार्यकर्ताओं की मौत, ममता-अभिषेक की सुरक्षा भी हटाई

पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे होगा। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने बताया कि 8 मई को विधायक दल की बैठक होगी। वहीं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के आवास से अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा हटा दी गई। हालांकि उन्हें पहले की तरह Z-कैटेगरी सुरक्षा मिलती रहेगी। तमिलनाडु में TVK चीफ विजय ने बुधवार को लोकभवन में राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले AIADMK और कांग्रेस दोनों में TVK को समर्थन देने की होड़ सी दिखी। दोपहर एक बजे कांग्रेस नेता खुद TVK के दफ्तर पहुंचे और अपना समर्थन पत्र सौंपा।

बंगाल में भड़की हिंसा

बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से हिंसा शुरू हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की हत्या हुई। इनमें भाजपा और TMC के 2-2 कार्यकर्ता हैं।

कोलकाता के न्यू मार्केट में मंगलवार रात भीड़ ने TMC के पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली स्थित बामनघेरी इलाके में मंगलवार रात गश्त कर रही पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसमें पांच सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

टीवीके को बहुमत के लिए 11 विधायकों की जरूरत

234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके की 108 सीटें हैं, लेकिन विजय दो सीटों पर जीते हैं, इसलिए एक सीट छोड़ने पर यह 107 रह जाएंगी। कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत 118 ही रहेगा, इसलिए टीवीके को 11 और विधायक चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिला है। कौन-कौन सी पार्टी उन्हें समर्थन देंगी यह साफ नहीं है। टीवीके ने बुधवार को अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को महाबलीपुरम के चेंगलपट्टू स्थित फोर पॉइंट्स नाम के रिसॉर्ट में शिफ्ट कर दिया है।

सम्पादकीय

अपेक्षित और अप्रत्याशित

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से जहां असम, केरलम और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के परिणाम अपेक्षा के अनुरूप सिद्ध हुए, वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के नतीजे अप्रत्याशित रहे। बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने इसलिए चौंकाया, क्योंकि जहां बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सत्ता विरोधी माहौल का सामना करने के बाद भी इसकी आशा शायद ही किसी को रही हो कि उसके लिए सौ सीटों तक पहुंचना भी कठिन हो जाएगा और भाजपा दौ सौ सीटों के निकट पहुंच जाएगी, वहीं तमिलनाडु में नए बने दल टीवीके के बारे में कम ही लोगों ने कमजोर सा अनुमान लगाया था कि वह सत्ता के निकट पहुंच जाएगी।

बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन की पराजय यह बताती है कि जो क्षेत्रीय नेता अपनी सत्ता को खुद की निजी जागीर में बदल लेते हैं, उन्हें जनता अधिक समय तक सहन नहीं करती। तमिलनाडु में टीवीके के जोसेफ विजय ने वह कर दिखाया, जो एक समय आंध्र में एनटी रामाराव और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था-पहली बार में ही बंपर जीत।

विजय की जीत का महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने छह दशक बाद द्रविड़ दलों को तमिलनाडु की सत्ता से बाहर कर दिया। बंगाल में भी भाजपा ने कांग्रेस, वाम दलों के लंबे शासन के बाद 15 वर्षों तक शासन करने वाली तृणमूल कांग्रेस को बाहर का दरवाजा दिखा दिया। बंगाल में प्रचंड जीत के साथ ही भाजपा ने पूर्वोत्तर के साथ पूर्वी भारत पर बढ़त हासिल कर ली।

बंगाल में जो राजनीतिक लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी, उसमें भाजपा की इतनी बड़ी जीत यह बताती है कि ममता का शासन कुशासन का पर्याय बन गया था और मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी राजनीति एवं बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ की गंभीर समस्या की अनदेखी ने बहुसंख्यक समुदाय को भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का काम किया। भाजपा के पूर्व संस्करण जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह राज्य में भाजपा की जीत ने यह भी रेखांकित किया कि उसके विस्तार और बढ़ते प्रभाव का सिलसिला तेज होने वाला है। इस जीत ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह के कद को और अधिक बढ़ाने का काम किया है।

2026 की भाजपा वह नहीं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद निस्तेज दिखने लगी थी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल यह प्रतीति कराने लगे कि अब उनका नंबर आएगा। नि:संदेह अब बंगाल में भी डबल इंजन सरकार होगी, लेकिन इसके साथ ही भाजपा के सामने यह चुनौती भी आ खड़ी हुई है कि वह राज्य की जनता से किए गए अपने वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे और इस राज्य को राजनीतिक हिंसा एवं घुसपैठियों से मुक्त करने के साथ फिर से पटरी पर लाए। पांच राज्यों के चुनाव नतीजे इसलिए भाजपा का अतिरिक्त उत्साहवर्धन करने वाले हैं, क्योंकि उसने असम में तीसरी बार कहीं बड़े अंतर से जीत हासिल की। इसके साथ ही केरलम और तमिलनाडु में भी अपने लिए कुछ जगह बनाई। पुडुचेरी में उसके समर्थन वाली सरकार का फिर से बनना भी कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वह असम के साथ यहां भी सत्ता विरोधी माहौल को दरकिनार करने में सफल रही।

ऐसा न तो बंगाल में ममता कर सकीं, न केरलम में विजयन और न ही तमिलनाडु में स्टालिन। कांग्रेस इससे प्रसन्न हो सकती है कि केरलम के रूप में एक और राज्य उसके हाथ आ गया, पर असम में वह जिस तरह पराजित हुई और यहां तक कि उसके सबसे प्रमुख नेता गौरव गोगोई भी हार गए, वह उसके लिए गहन आत्मचिंतन का विषय बनना चाहिए। वह भले ही केरलम में अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने जा रही हो, लेकिन पांच राज्यों के नतीजे यही कह रहे हैं कि उसके नेतृत्व वाला गठबंधन आइएनडीआइए और कमजोर हो गया है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की चली सुनामी के सियासी मायने दूरगामी महत्व वाले

केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति-संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो भय हारा और भरोसा जीता है। भद्रलोक के हृदय परिवर्तन से सोनार बंगला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और बंगलादेशी घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी।

इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तेवरों का भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के बलिदानी कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है।

देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हौसलाअफजाई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है।

दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएस/भाजपा नेताओं-कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी।

लिहाजा, इस अभूतपूर्व विजय के प्रमुख राजनीतिक निहितार्थ/मायने इस प्रकार होंगे–

1. पूर्वी भारत में भाजपा का निर्णायक विस्तार

पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा।

2. ममता बनर्जी की राष्ट्रीय भूमिका कमजोर पड़ना

ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी राष्ट्रीय विकल्प वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी।

3. कांग्रेस और वामपंथ का लगभग राजनीतिक अंत

पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तृणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है।

4. हिंदुत्व और कल्याणकारी राजनीति मॉडल की सफलता

भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी।

5. बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव

बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान-आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है।

6. 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय होगी

भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है।

7. संघ और भाजपा संगठन की रणनीति को वैधता

पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी।

8. केंद्र-राज्य संबंधों में नया समीकरण

अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है।

ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ ; भारत की बदलती युद्धनीति और सतत संघर्ष

आज ऑपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूर्ण हो गया है। एक ऐसा सैन्य अभियान, जिसने भारत की रणनीतिक और सुरक्षा नीति को मूल रूप से बदल दिया। 6-7 मई 2025 की रात संचालित यह अभियान भारत के प्रतिक्रियात्मक राष्ट्र से सक्रिय और निर्णायक शक्ति में परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरा। इसकी पृष्ठभूमि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में निहित थी, जिसने केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि भारत की आंतरिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास और पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था को भी आघात पहुँचाया। अनंतनाग जिले के शांत क्षेत्र में पर्यटकों और निहत्थे नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए इस हमले में लगभग 26 लोगों की जान गई। जांच में इसके तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों, विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा, से जुड़े पाए गए। पहले जहाँ ऐसे हमलों के बाद केवल कूटनीतिक

लेखक - कर्नल देव आनंद लोहामरोर, सुरक्षा एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के जानकार (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूतपूर्व सैनिक विकास समिति)

विरोध और सीमित प्रतिक्रिया देखने को मिलती थी, वहीं इस बार भारत का संदेश स्पष्ट था अब केवल 'प्रतिक्रिया' नहीं, बल्कि 'प्रतिकार' होगा। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग करने के प्रयास तेज किए और यह स्थापित किया कि भारत की हर कार्रवाई 'काउंटर-टेरर ऑपरेशन' के दायरे में होगी। साथ ही नियंत्रण रेखा (LoC) पर निगरानी को सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन रिकॉनिसेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस के माध्यम से और अधिक मजबूत किया गया, जबकि आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध तीव्र अभियान चलाए। इन्हीं तैयारियों का परिणाम था 'ऑपरेशन सिंदूर ', जिसके अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने मात्र 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण, लॉन्चिंग और हथियार भंडारण केंद्र थे। राफेल जैसे उन्नत लड़ाकू प्लेटफॉर्म, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन और आधुनिक आर्टिलरी के समन्वित उपयोग ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अब 'स्पीड, सरप्राइज़ और सर्जिकल एक्यूरेसी' पर आधारित युद्ध नीति में प्रवेश कर चुका है। इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि भारत ने स्थापित कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए वह कहीं भी निर्णायक कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सैन्य क्षमता रखता है। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा प्रभाव पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे 'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' नैरेटिव को कमजोर करना था। दशकों तक पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध के भय का उपयोग कर प्रॉक्सी आतंकवाद को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु सीमा के नीचे रहकर भी नियंत्रित और सटीक सैन्य कार्रवाई संभव है। इससे दक्षिण एशिया की प्रतिरोधक क्षमता में बड़ा बदलाव आया। ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम इसके बाद सामने आया, जब पाकिस्तान ने पारंपरिक सैन्य जवाब के बजाय ड्रोन, यूएवी, लोइटरिंग म्यूनिशन और क्वाडकॉप्टर के माध्यम से हाइब्रिड युद्ध रणनीति अपनाई। इससे स्पष्ट हो गया कि आधुनिक युद्ध अब केवल टैंक, तोप और लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और मानवरहित प्रणालियाँ भविष्य के युद्धक्षेत्र का केंद्र बनेंगी। भारत ने इस चुनौती का सामना राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य कमान के सशक्त समन्वय से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के संचालनात्मक समन्वय में भारत ने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम (IADS) को सक्रिय किया। रडार नेटवर्क, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, RF जैमिंग, GPS स्पूफिंग और त्वरित इंटरसेप्शन क्षमताओं ने दुश्मन के ड्रोन और हवाई खतरों को लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने सीडीएस संरचना और त्रि-सेवा समन्वय (Tri-Service Jointness) के महत्व को भी सिद्ध किया। इस संघर्ष ने स्पष्ट किया कि भविष्य के युद्ध अलग-अलग सेनाओं के स्वतंत्र दृष्टिकोण से नहीं लड़े जा सकते। सेना, वायुसेना, नौसेना, खुफिया एजेंसियों, साइबर यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क के बीच समन्वय अब अनिवार्य हो चुका है। इस ऑपरेशन ने आधुनिक युद्ध में इंटेलिजेंस फ्यूजन के महत्व को भी स्थापित किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस (HUMINT), टेक्निकल इंटेलिजेंस (TECHINT), सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन निगरानी, साइबर मॉनिटरिंग और सिग्नल इंटरसेप्शन को एकीकृत कर संयुक्त ऑपरेशनल ढाँचा तैयार किया गया। इससे लक्ष्य चयन सटीक हुआ और कम समय में अधिक प्रभाव उत्पन्न किया जा सका। भविष्य के युद्ध अब केवल संख्या बल पर नहीं, बल्कि सूचना और तकनीकी श्रेष्ठता पर निर्भर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने 'आत्मनिर्भर भारत' की रक्षा नीति की सफलता को भी उजागर किया। 'अरुधरा' और 'अश्विनी' जैसे स्वदेशी रडार सिस्टम, एंटी-ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संघर्ष ने स्पष्ट किया कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता है। 7 से 10 मई के बीच संघर्ष सीमित लेकिन तीव्र सैन्य टकराव में बदल गया, जिसमें ड्रोन, मिसाइल, आर्टिलरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का व्यापक उपयोग हुआ। पाकिस्तान ने जवाबी प्रयास किए, लेकिन भारत ने रणनीतिक बढ़त बनाए रखते हुए एस्केलेशन कंट्रोल कायम रखा। इससे स्पष्ट हो गया कि भविष्य के युद्ध तेज, सीमित, तकनीक-आधारित और राजनीतिक रूप से नियंत्रित होंगे।

विशेष आलेख /राशिफल

बंगाल में भाजपा ने किया कमाल

यदि पांच राज्यों-पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी के चुनाव परिणामों को समग्र रूप में देखा जाए, तो एक व्यापक तस्वीर उभरती है। इस तस्वीर में दो घटनाएं विशेष रूप से ऐतिहासिक प्रतीत होती हैं-बंगाल में भाजपा की उल्लेखनीय बढ़त और तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी टीवीके का प्रभावशाली प्रदर्शन। हालांकि असम में भाजपा की लगातार तीसरी जीत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बंगाल और तमिलनाडु की घटनाएं राजनीतिक दृष्टि से अधिक दूरगामी प्रभाव वाली हैं। बंगाल में एक बड़े मुस्लिम मतदाता वर्ग के तृणमूल कांग्रेस के संगठित समर्थन के बावजूद भाजपा की बढ़त सामान्य घटना नहीं। वैसे तो असम में भी उल्लेखनीय मुस्लिम आबादी के बावजूद भाजपा की जीत ने कई स्थापित राजनीतिक मिथकों को तोड़ा है, पर असम और बंगाल की राजनीति के स्वरूप और सत्ता संरचना में मौलिक अंतर है। बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल और सत्ता संरचना विकसित की थी, उसमें किसी अन्य दल के लिए प्रभावी चुनौती पेश करना कठिन था। ऐसे में भाजपा की यह सफलता केवल चुनावी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन का संकेत है कि बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पिछले एक दशक से चुनावी रुझानों का यह एक प्रमुख पहलू लगभग हर राज्य में दिखाई देता है कि हिंदुत्व, संस्कृति और धार्मिक पहचान के प्रति हिंदुओं के एक व्यापक पुनर्जागरण ने एक स्थायी मतदाता आधार का निर्माण किया है। यह आधार ऐसा है, जो संतुष्टि, असंतोष या आंशिक नाराजगी के बावजूद किसी न किसी रूप में भाजपा या उसके सहयोगी दलों के पक्ष में झुकाव बनाए रखता है और कई बार उसकी अनुपस्थिति में वैचारिक रूप से निकट दलों की ओर भी स्थानांतरित हो जाता है।

यह प्रवृत्ति पांचों राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिली। भाजपा स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के साथ-साथ चुनावी विमर्श को राष्ट्रीय विषयों से जोड़ने की रणनीति अपनाती रही है। इससे मतदाताओं के साथ उसका सीधा भावनात्मक और वैचारिक संवाद स्थापित होता है। भाजपा ने बंगाल और असम में राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उभारा, जो चुनावी एजेंडे के केंद्र में रहे। मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रमों ने भी चुनावी माहौल को प्रभावित किया। इन्होंने महिला मतदाताओं के बीच एक सकारात्मक संदेश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वास्तव में बंगाल के परिणाम ने केवल उन्हें ही चौंकाया है, जो जमीनी सच्चाई के साथ मतदाताओं और विशेष रूप से हिंदुओं के बड़े वर्ग के अंदर बदलाव की छटपटाहट को महसूस नहीं कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की सत्ता और पूरी राजनीति को निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों में सौंप दिया था। इससे कट्टरपंथी तत्वों को मिले प्रत्यक्ष-परोक्ष संरक्षण और प्रोत्साहन के कारण पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक भय और तनाव की स्थिति में कायम हो गई थी। वे कहने लगे थे कि मतदाता अपनी इच्छा से नहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की चाहत से मतदान करें या घर बैठें, अन्यथा हिंसा, दमन, उत्पीड़न और पलायन का दंश झेलें। साइलेंट रिगिंग बंगाल की मुख्य चुनावी प्रवृत्ति रही है। पहले इसी रास्ते वाम मोर्चा ने लगातार जीत सुनिश्चित की और फिर ममता ने भी अपनी पूरी पार्टी को उससे ज्यादा हिंसक और दमनकारी तत्वों में परिणत कर दिया। पलायन या हिंसा की सर्वाधिक शिकार महिलाएं होती हैं। इसी कारण इनका बहुत बड़ा मत तृणमूल के बजाय भाजपा को गया। जो लोग भाजपा पर हिंदुओं के ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, वे सतही विश्लेषण कर रहे हैं। वास्तव में बंगाल में राजनीतिक संघर्ष वास्तविक लोकतंत्र की पुनर्स्थापना तथा सत्ता संस्कृति को सर्वसमावेशी बनाने का था। यह जिम्मेदारी मुख्यतः प्रदेश के हिंदुओं को ही लेनी थी। हिंदुओं के अंदर अगर यह भाव पैदा हुआ कि इस सरकार के रहते हमारा अस्तित्व संकट में है, तो इसके कारण अत्यंत गहरे हैं। बांग्लादेश की हिंसक घटनाओं ने हिंदुओं के इस मनोविज्ञान को सशक्त किया कि हमें कुछ हद तक जान की बाजी लगानी होगी। इसके अलावा एसआइआर में मृत, संदिग्ध और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के कारण फर्जी मतदाताओं का खेल खत्म हो गया। सवा दो लाख केंद्रीय बलों की उपस्थिति, चुनाव के बाद भी सुरक्षा बलों के बने रहने की घोषणा, दूसरे राज्यों के अधिकारियों की चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति, प्रदेश के अधिकारियों का व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण या चुनाव प्रक्रिया तक कार्य मुक्ति तथा चुनावी हिंसा वाले चिह्नित व्यक्तित्वों के विरुद्ध कार्रवाई एवं सतर्क दृष्टि आदि ने भय और संशयग्रस्त मतदाताओं के अंदर सुरक्षा को लेकर आश्वस्त किया, जिससे चुनावी माहौल में बड़ा परिवर्तन आया। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मतदाताओं को पहले दिन से यह विश्वास दिलाने की रणनीति अपनाई कि हम सत्ता में आ रहे हैं तथा किसी के साथ अन्याय हुआ तो पूरी पार्टी खड़ी रहेगी।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष — आज मन में किसी बात की चिंता रहेगी। स्वास्थ्य का मामला कमजोर रहेगा। दफ्तर में उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।

सिंह — आपकी वाणी और व्यवहार के कारण असमंजस की स्थिति न उत्पन्न हो, इसका ध्यान देने की जरूरत है। आवेश और उग्रता के कारण किसी से तकरार न हो, इसका ध्यान रखें।

धनु — आप आज के दिन पूरी तरह से आमोद-प्रमोद में बिताना पसंद करेंगे। अपने दैनिक कामों से मुक्त होकर अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकेंगे। मित्रों के बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा।

वृषभ — आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। नौकरी और व्यापार में भी लाभ के संकेत हैं। मित्रों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकते हैं।

कन्या — आज आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा और आप मानसिक रूप से अस्वस्थ्य रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है।

मकर — आज आप आर्थिक जिम्मेदारियों के प्रति ध्यान देंगे तथा कहीं निवेश की योजना भी बना सकेंगे। आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

मिथुन — आप अपने दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी बौद्धिक प्रतिभा दिखेगी।

तुला — आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा। आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले सगे-संबंधियों के समाचार मिलेंगे, इससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे।

कुंभ — अति आवश्यक काम को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आपकी रचनात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी। वैचारिक दृढ़ता एवं मानसिक स्थिरता के कारण काम सफल रहेंगे।

कर्क — आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। घर का वातावरण आनंदप्रद रहेगा। शारीरिक रूप से स्वस्थता और मानसिक रुप से खुशी मिलेगी।

वृश्चिक — आज आपको किसी भी नए काम का आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है। अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखें। दोस्त के रूप में छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें।

मीन — निजी विचारों को छोड़कर दूसरों के विचारों को अपनाने की जरूरत है। घर तथा परिजनों के काम करते समय आपके लिए समाधानकारी व्यवहार अपनाना उचित रहेगा।

महत्वपूर्ण बैठक | बस टर्मिनलों के पुनर्विकास को लेकर बैठक

सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित होंगे आधुनिक बस पोर्ट:भजनलाल शर्मा

जयपुर (नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, जिससे प्रदेश की आमजन का सफर सुगम हो और विकास को नई गति मिले। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बस टर्मिनलों का पुनर्विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रदेश के बस टर्मिनलों के पुनर्विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चयनित जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आधुनिक बस पोर्ट विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस पोर्ट क्षेत्रीय परिवहन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होंगे। जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को बस पोर्ट्स के प्रभावी संचालन, सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं दीर्घकालिक रखरखाव के लिए समग्र एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रस्तावित बस पोर्ट्स पर राजस्थान पथ परिवहन निगम एवं निजी बसों का बेहतर समन्वय से नियमित एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित हो। इस दौरान जानकारी दी गई कि बजट घोषणा की अनुपालना में यात्रियों को आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, बूंदी सहित चयनित जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त बस पोर्ट विकसित किये जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पाँच राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने सभागार एवं डिजिटल म्यूजियम का भी किया अवलोकन

स्पीकर्स ने राजस्थान विधानसभा भवन, सदन व म्यूजियम को बताया शानदार

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान विधानसभा परिसर में मंगलवार को पर्यावरण, आयुर्वेद एवं भारतीय ज्योतिष विज्ञान को समर्पित दो अनूठी वाटिकाओं – हर्बल वाटिका एवं नक्षत्र वाटिका का विधिवत उद्घाटन सम्पन्न हुआ। यह उद्घाटन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने देश के पांच राज्यों के विधान सभा अध्यक्षगण के साथ किया। इस गरिमामय अवसर पर मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, उत्तरप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष श्रीमती सुरमा पाढ़ी एवं सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री मिंगमा नोर्बू शेरपा की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यक्रम में राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल एवं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली भी उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम राजस्थान विधानसभा में लोकसभा द्वारा गठित समिति के पीठासीन अधिकारियों की बैठक के अवसर पर सम्पन्न हुआ। देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा की स्थापना का यह वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

इस महोत्सव के तहत ही यह दो वाटिकाएं निर्मित की गई है। पांचों राज्यों के स्पीकर्स ने राजस्थान विधान सभा के भवन, सदन व म्यूजियम को शानदार बताते हुए कहा कि म्यूजियम ज्ञानवर्धक है।

न्यूज इन बॉक्स

कानोड़िया कॉलेज में सर्टिफिकेट वितरण समारोह: डिजिटल स्किल्स से छात्राओं को मिल रही नई पहचान

जयपुर(नि.सं.)। कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर के कंप्यूटर विज्ञान विभाग द्वारा 06 मई को इंटर्नशिप एवं कौशल विकास प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों, वेब डिजाइनिंग यूआई/यूएक्स एवं ग्राफिक डिजाइनिंग, के सफलतापूर्वक समापन पर छात्राओं के लिये प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल ने प्रमाण-पत्र वितरित किये। वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में डिजिटल क्रिएटिविटी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यूआई/यूएक्स और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कौशल आज के युवाओं के लिए अनिवार्य बन चुके हैं। इन विशेष पाठ्यक्रमों का उद्देश्य अकादमिक ज्ञान और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करना है। तीन माह की अवधि में 47 छात्राओं ने उपयोगकर्ता-केंद्रित वेब इंटरफेस तथा प्रोफेशनल विजुअल डिजाइन तैयार करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंटर्नशिप के माध्यम से छात्राओं को वास्तविक परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिला।

झाला रानी शाखा ने शुरू किया विरासत के साथ सेल्फी

पर्यटन और विरासत संरक्षण के लिए गढ़ गार्डन में बांधे परिंडे

झालावाड़ (वि.सं.)। झालावाड़ में झाला रानी शाखा ने पर्यटन और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विरासत के साथ सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य आमजन में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें अपनी ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। अभियान के तहत, शाखा के सदस्यों ने गढ़ गार्डन में सेवा कार्य भी किया। भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान गढ़ गार्डन में कुल 20 परिंडे बांधे गए, जबकि 15 परिंडे आमजन को उनके घरों पर लगाने के लिए वितरित किए गए। इस सेवा कार्य का मुख्य उद्देश्य पक्षियों को गर्मी से राहत पहुंचाना और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने भी सहयोग प्रदान किया। समिति से जुड़े सालिग्राम दांगी ने झाला रानी शाखा के प्रयासों की सराहना की।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

नदी बेसिन मास्टर प्लान विकसित राजस्थान-2047 के अनुरूप करें तैयार : मुख्य सचिव

जयपुर (नि.सं.)। वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय स्थित चिंतन कक्ष में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल संसाधन प्रबंधन, संरक्षण एवं विभाग की योजना से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से सुदृढ़ योजना निर्माण एवं सतत मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने एवं जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव द्वारा मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ को घग्गर नदी के मानसून अवधि में बाढ़ और जल उपलब्धता और संभावित उपयोग का अध्ययन करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही, सभी बेसिन मुख्य अभियंता एवं बेसिन अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को अपने-अपने संभाग में स्थित नदी बेसिनों की अद्यतन प्रभावी योजना एवं नदी बेसिन मास्टर प्लान विकसित राजस्थान–2047 को ध्यान में रखते हुए शीघ्र तैयार करने के निर्देश प्रदान किए। इसमें जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण के आयुक्त श्री अभय कुमार ने राजस्थान नदी बेसिनों की जानकारी प्रस्तुत दी। प्राधिकरण के मुख्य अभियंता श्री राज पाल सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। बैठक में जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें सतही जल की उपलब्धता, रावी-ब्यास से प्राप्त जल, भूजल विकास की स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों में जल की मांग (सिंचाई, पेयजल एवं औद्योगिक उपयोग), नहरों में जल परिवहन के दौरान होने वाली हानि तथा प्रमुख परियोजनाएं शामिल रहीं।

सांध्य चौपाल में आमजन के अभाव - अभियोग सुने

कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा ग्राम -2026 : सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री तथा चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुधवाली में सांध्य चौपाल में आमजन के अभाव – अभियोग सुने तथा ग्राम रथ अभियान कार्यक्रम में शिरकत कर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए आमजन से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)- 2026 में अधिकतम भागीदारी निभाने की अपील की। इस अवसर श्री गहलोत ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाएं समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। छात्रवृत्ति, पेंशन, स्वरोजगार एवं विभिन्न सहायता योजनाओं के माध्यम से सरकार हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने राजस्थान को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लिया है। आज राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्धता करवाई जा रही है।

6 साल के बेटे को जहर देकर मारा,पिता को उम्रकैद

CRPF में कॉन्स्टेबल था आरोपी; पत्नी की हर निशानी को खत्म करना चाहता था

अलवर (वि.सं.)। 6 साल के बेटे को जहर देकर मारने वाले दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बच्चे के नाना ने अपने बयानों में कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि आरोपी ने उनकी बेटी की भी हत्या की थी। वहीं दोनों दोहितियों को भी मारने की कोशिश की थी।

बच्चे की मौत के 6 साल बाद अब अलवर के एडीजे कोर्ट नंबर-3 ने फैसला सुनाया है। आरोपी CRPF में कॉन्स्टेबल था। जनवरी में ही वीआरएस लिया था। सरकारी वकील अजीत यादव ने बताया कि मामला 19 अगस्त 2020 का है। आरोपी मामचंद निवासी लीली, मालाखेड़ा को उसके बेटे कुनाल की हत्या करने पर सजा सुनाई गई है।

राष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण

नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग की दी जानकारी

जयपुर(नि.सं.)। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम पर विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल को राज्य के फीडबैक लेकर देश भर में लागू किया जाएगा। संस्थान-आधारित नवजात देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस पहल में ऑक्सीजन के सही और सुरक्षित उपयोग के साथ-साथ सी-पेप को जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में शामिल करने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से एफबीएनसी के अंतर्गत इस संबंध में 4 एवं 5 मई को दो दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पायलट प्रशिक्षण सह-प्रशिक्षक प्रशिक्षण जे के लोन अस्पताल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जोगाराम ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता को साक्ष्य-आधारित ऑक्सीजन थेरेपी प्रथाओं में सुदृढ़ करना है।

उन्होंने बताया कि हाइब्रिड लर्निंग पद्धति पर आधारित इस पायलट प्रशिक्षण में प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं मेडिकल कॉलेजों से बाल रोग विशेषज्ञ एवं स्टाफ नर्स ने भाग लिया है। इसमें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, पल्स ऑक्सीमेट्री द्वारा मॉनिटरिंग तथा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग के प्रोटोकॉल्स के बारे में राज्य के फीडबैक लिए गए।

दूध में केमिकल और डिटर्जेंट मिलाना जहर देने के समान

नकली दूध बनाने वाले 9 दोषियों को 10-10 साल जेल, 5-5 लाख जुर्माना लगाया

धौलपुर (वि.सं.)। दूध में फॉर्मोलिन जैसे रसायनों का उपयोग अत्यंत घातक है। जिसके सेवन से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूध में केमिकल व लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यह किसी को जहरीला पदार्थ देने के समान है। धौलपुर जिला एवं सत्र कोर्ट ने नकली दूध बनाने के मामले में यह टिप्पणी करते हुए नौ आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच लाख रु.के आर्थिक दंड से दंडित किया।

बोलेरो और एम्बुलेंस की भिड़ंत

जयपुर में बोलेरो-एम्बुलेंस में भिड़ंत, 7 घायल:डिवाइडर कूदकर पलटी बोलेरो

जयपुर(नि.सं.)। जयपुर में बोलेरो और एम्बुलेंस की भिड़ंत हो गई। बस को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर बोलेरो डिवाइडर कूदकर रॉग साइड पहुंच पलटी खा गई थी। हरमाड़ा थाना पुलिस ने हादसे में बोलेरो व एम्बुलेंस में सवार घायल सात लोगों को कांवटिया हॉस्पिटल पहुंचाया। SHO (हरमाड़ा) उदय सिंह यादव ने बताया- हादसा सुबह करीब 8:45 बजे हरमाड़ा घाटी में हुआ। एक बोलेरो गाड़ी में

सवार चार लोग चौमूं की ओर से जयपुर जा रहे थे। हरमाड़ा घाटी में लोक परिवहन बस को ओवरटेक करने के दौरान बोलेरो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बोलेरो गाड़ी डिवाइडर क्रॉस कर रॉग साइड पहुंच सामने से आ रही एम्बुलेंस को टक्कर मारकर पलटी खा गई। हादसे में बोलेरो और एम्बुलेंस में सवार 7 लोग घायल हो गए। हरमाड़ा थाना पुलिस को सूचना देने के साथ ही राहगीरों ने घायलों को जैसे-तैसे क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकाला। हरमाड़ा थाना पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत कांवटिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद चार जनों को छुट्टी दे दी गई। घायल बीना देवी, मनीषा और देपेन्द्र का इलाज चल रहा है।

खेत तालाब योजना | पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा

खेत तालाब योजना से किसान की बढ़ी आय जल संरक्षण से सशक्त हो रही खेती, ग्रामीणों को मिल रहा सीधा लाभ

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार जिले में संचालित ग्राम रथ अभियान ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से जहां एक ओर आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो रही है, वहीं दूसरी ओर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है।ग्राम पंचायत घिनाई के ग्राम सबलपुरा में आयोजित ग्राम रथ अभियान के दौरान किसान श्री लालचंद पुत्र श्री नाथूराम यादव ने खेत तालाब योजना का लाभ लेकर

अपनी खेती को सशक्त बनाया। उन्होंने बताया कि वे खेती पर निर्भर हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण उनकी खेती प्रभावित हो रही थी और खेत खाली पड़े रहते थे। कृषि विभाग के संपर्क में आने के बाद उन्हें खेत तालाब निर्माण योजना की जानकारी मिली और उन्होंने इसका लाभ लिया। विभाग द्वारा उन्हें लगभग 1.35 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने अपने खेत में तालाब का निर्माण करवाया।

अब वर्षा का पानी तालाब में संग्रहित हो रहा है, जिसका उपयोग वे सिंचाई के लिए कर रहे हैं।

इससे उनकी फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है और आय में भी सुधार हुआ है। लाभार्थी ने योजना का लाभ मिलने पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए अन्य किसानों से भी अपील की कि वे जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाएं और अपनी खेती को मजबूत बनाएं।

...यहां रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक
11 घंटों का लॉकडाउन!

राजस्थान के भारत-पाक बॉर्डर पर अचानक हाई अलर्ट, मजिस्ट्रेट ने लगाई कई पाबंदियां

लोक टुडे। श्रीगंगानगर

भारत-पाक सीमा पर बढ़ते सुरक्षा खतरों और घुसपैठ की आशंका के बीच श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बढ़ती राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और घुसपैठ की आशंकाओं ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इसी के मद्देनज़र जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सरहद से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

शाम 7 से सुबह 6 तक पूर्ण पाबंदी

5 मई 2026 को जारी इस आदेश के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने कुछ कड़े नियम तय किए हैं।

- आवागमन पर रोक : रात 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी आम नागरिक का

सीमा से सटे 3 किमी क्षेत्र में घूमना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि यहां इन 11 घंटे तक 'लॉकडाउन' जैसी स्थिति रहेगी।

- रोशनी और शोर पर लगाम : सीमा क्षेत्र में तेज प्रकाश का उपयोग, लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड और पटाखों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

- सुरक्षा घेरा : यह आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

15 सितंबर 2026 तक प्रभावी

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 का प्रयोग करते हुए यह आदेश प्रभावी किया है। यह आदेश आगामी 15 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकृत कर्मचारी, जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्हें इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

सीमापार से खतरे की आशंका

अचानक से 3 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरह प्रतिबंधित करना और रात के समय रोशनी तक पर पाबंदी लगा देना, कई अनसुलझे सवालों को जन्म दे रहा है। क्या सीमा पार से किसी बड़े ड्रोन मूवमेंट की आशंका है? या फिर राष्ट्रविरोधी तत्व किसी गुप्त सुरंग या घुसपैठ के फिराक में हैं? प्रशासन ने इसे 'जन-सुरक्षा और शांति भंग की आशंका' बताया है, लेकिन सरहद पर बढ़ती यह सख्ती किसी बड़े ऑपरेशन या इनपुट की ओर इशारा कर रही है।

किसानों के लिए विशेष रियायत :

खेती-किसानी राजस्थान की जीवन रेखा है। बॉर्डर के पास रहने वाले किसानों को सिंचाई के लिए रात में भी खेतों में जाना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने एक विशेष रियायत दी है। यदि रात के समय सिंचाई के लिए जाना अनिवार्य है, तो किसानों को सीमा सुरक्षा बल या सेना के अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के सीमा क्षेत्र में प्रवेश कानूनी अपराध माना जाएगा।

प्रतिबंधित इलाके में 6 उपखंड :

यह प्रतिबंध केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि श्रीगंगानगर जिले के उन सभी प्रमुख हिस्सों को कवर करता है जो सीधे पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। इनमे श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घडसाना शामिल है।

रीको-पीडब्ल्यूडी मिलकर करेंगे सड़कों का निर्माण, औद्योगिक कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

लोक टुडे। जयपुर

रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जायेगा। इसके अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जायेगा।

रीको के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी। इससे पूर्व भी रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने हेतु खिजुरीवास टोल प्लाजा से टपूकड़ा तक राज्य राजमार्ग संख्या-25 के चौड़ीकरण एवं नाले के निर्माण कार्य के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से 50 प्रतिशत लगभग 37 करोड़ रुपये वहन करने की स्वीकृति दी है। रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम संचालन को सुगम बनाने के लिए रीको लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है।

भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे से विभिन्न सेवाओं पर चर्चा

लोक टुडे। जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफ्रे से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, महिला एवं बाल विकास, पोषण, शिक्षा तथा बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े विषयों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अभियान व्यापक स्तर पर संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में संचालित मा योजना(मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना) से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हुई हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में यूनिसेफ के सहयोग से नवाचार किये जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी प्रभावी कार्य किया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा कुलदीप रांका ने कहा कि यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से संचालित युवा सेतु कार्यक्रम युवाओं के लिए अवसरों का सशक्त माध्यम बन रहा है। कार्यक्रम के तहत युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं नवाचार आधारित गतिविधियों के परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनकी तकनीकी दक्षता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है। शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास पूनम ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूनिसेफ के सहयोग से आशा कार्यकर्ताओं को ग्रोथ मॉनिटरिंग तथा डेटा वैलिडेशन संबंधी प्रशिक्षण को और अधिक मजबूत किया जाएगा। सिंथिया मैककैफ्रे ने कहा कि यूनिसेफ की आगामी वर्ष 2026-29 की कार्ययोजना के अंतर्गत यूनिसेफ नीति निर्माण, तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने एवं महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएंगे। एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से विकास के प्रमुख क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों को दूर कर विकसित राजस्थान के लक्ष्य को गति दी जाएगी।

... क्या प्रशासन कर रहा किसी हादसे का इंतजार ?

खुले ट्रैक्टर में कचरा ढोना सड़क पर चलने वालों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। एक तरफ सफाई का दिखावा, दूसरी तरफ हवा में उड़ता कचरा। यह स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिना तिरपाल या ढक्कन के कचरा ले जाना नियमों का उल्लंघन है। शहर को साफ रखने के चक्कर में सड़कों को गंदा किया जा रहा है। नगर निगम की नाक के नीचे खुलेआम लापरवाही का आलम दिखना आम बात हो गयी है।

अजमेर डिस्कॉम के सभी जिलों में दो ब्लॉक सप्लाई जल्द

प्रदेश के 24 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को मिल रही दिन में बिजली

जीएसएस तथा ट्रांसमिशन क्षमता वृद्धि के कार्यों को दें गति -ऊर्जा सचिव

जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष-2027 तक प्रदेश में किसानों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में अजमेर डिस्कॉम जल्द ही प्रदेश का पहला ऐसा विद्युत वितरण निगम होने जा रहा है जहां सभी जिलों में दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति सुलभ हो सकेगी। फिलहाल यहां नागौर एवं चित्तौड़गढ़ को छोड़कर शेष सभी जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को यह बिजली मिल रही है।

ऊर्जा विभाग की शासन सचिव एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बुधवार को विद्युत भवन में दो ब्लॉक सप्लाई को लेकर अजमेर एवं जोधपुर वितरण निगम के प्रबंध निदेशकों, प्रसारण निगम तथा जयपुर विद्युत वितरण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान विद्युत तंत्र को मजबूत कर प्रसारण निगम एवं वितरण निगमों से संबंधित दिन में दो ब्लॉक सप्लाई की बाधाओं को दूर करने, ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि आदि विषयों पर समीक्षा की गई।

आरती डोगरा ने निर्देश दिए कि अजमेर डिस्कॉम के नागौर सर्किल में प्रसारण निगम द्वारा 220 केवी जीएसएस निर्माण तथा डिस्कॉम द्वारा इससे जुड़ने वाले 33 केवी के 4 सब स्टेशनों में ट्रांसमिशन क्षमता वृद्धि तथा इंटर कनेक्शन के कार्य आगामी जून माह तक पूर्ण कर लिए जाएं। उल्लेखनीय है कि नागौर जिले में प्रसारण निगम द्वारा 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन बिरलोका का निर्माण प्रगति पर है। इस जीएसएस के बनने से 33 केवी के चार सब स्टेशनों से दिन में दो ब्लॉक में सप्लाई दी जा सकेगी। इनके अतिरिक्त क्षमता वृद्धि एवं इंटर कनेक्शन के कार्य पूर्ण होने से 33 केवी के डेह, करनू, डेउ तथा कुरची स्थित जीएसएस से जुड़े क्षेत्रों में वितरण निगम तीन के स्थान पर दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति कर सकेगा।

औद्योगिक कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती : रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर करेंगे सड़कों का निर्माण

290 करोड़ रूपये की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग की अप्रोच सड़कों का सुदृढ़ीकरण

हिंद रफ्तार,जयपुर

रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जायेगा। इसके अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जायेगा।

रीको के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी।

इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी।

इससे पूर्व भी रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने हेतु खिजुरीवास टोल प्लाजा से टपूकड़ा तक राज्य राजमार्ग संख्या-25 के चौड़ीकरण एवं नाले के निर्माण कार्य के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से 50 प्रतिशत लगभग 37 करोड़ रुपये वहन करने की स्वीकृति दी है।

रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम संचालन को सुगम बनाने के लिए रीको लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है।

विकास की ओर राजसमंद ; उप मुख्यमंत्री ने सांगठकला में खोला सौगातों का पिटारा

रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याए सुनकर अधिकारियो को त्वरित समाधान के निर्देश

लोक टुडे। जयपुर

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सांगठकला में आयोजित समारोह में 67 करोड़ रूपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश के साथ-साथ राजसमंद में भी विकास कार्यों को गति मिली है। दिया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि गरीब, किसान, महिला, युवा एवं वंचित वर्गों के

सशक्तिकरण हेतु विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं, जिससे आमजन के जीवन स्तर में निरंतर सुधार हो रहा है।

योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिले :

समारोह में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति के समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि डबल इंजिन की सरकार का लक्ष्य केवल विकास कार्यों का विस्तार करना ही नहीं, बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करना भी है। इस अवसर पर कुंभलगढ़ विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, राजसमंद जिला कलक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इनकी मिली सौगात :

कार्यक्रम में सांगठकला से सहाडा गंगापुर वाया साकरोदा, सुन्दरचा, तासोल, खटामला एवं बिनोल तक 28.90 किलोमीटर लंबाई के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य रहा, जिसकी लागत 47.96 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त पुठोल में 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान किए गए लोकार्पण कार्यों में पसुन्द में श्मशान से तलाई कुआ राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक 80 लाख रुपये की लागत से निर्मित बीटी सड़क, सापोल से आत्मा रोड तक 3 करोड़ रुपये की लागत से बीटी सड़क निर्माण तथा एमड़ी में जे.के. स्कूल से भट्टखेड़ा मार्ग तक नहर के साथ 2.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सड़क शामिल हैं। वहीं शिलान्यास किए गए कार्यों में पुठोल क्षेत्र के बागोटा में खरवड़ों की भागल से सालवी बस्ती एवं गुर्जरों की भागल तक 50 लाख रुपये की लागत से सड़क निर्माण, 2.50 करोड़ रुपये की लागत से झांझर से पोदावली मार्ग वाया कलखेत सड़क निर्माण, 3 करोड़ रुपये की लागत से सांगठकला के बीड़ों की भागल से गोवल तक बीटी सड़क निर्माण, 1.59 करोड़ रुपये की लागत से सांगठकला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन का निर्माण तथा 5.11 करोड़ रुपये की लागत से सांगठ बांध एवं नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्य शामिल हैं। इस प्रकार कुल 67.46 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्य जनता को समर्पित किए गए।

रात्रि चौपाल में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं :

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत राज्यावास में आयोजित रात्रि चौपाल में सहभागिता कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याएं एवं सुझाव उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। उप मुख्यमंत्री ने चौपाल के दौरान एक-एक समस्या को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशील है और प्रशासन को जवाबदेह बनाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा, विकास अधिकारी भवानी शंकर सहित कई जनप्रतिनिधि-अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रिक, प्रकाशन, संपादक - नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, हटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रिक एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झेलना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) प्रकाशित प्रबंध संपादक - पी.के.बूजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)